DAINIK JAGRAN
06/03/2017

Media/LKO/010/2017

चीनी आयात से बढ़ेगा गन्ना मूल्य भुगतान संकट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : गन्ना मूल्य बकाये के भुगतान संकट का समाधान आसान नहीं दिख रहा है। चीनी आयात की सुगबुगाहट से भुगतान समस्या और गहराने से आशंकित किसान व्यापक आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। वहीं मिल मालिकों की बेचैनी भी बढ़ी है।

गेहूं आयात शुल्क हटाने से किसानों की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। आयात को उदार कर देने से किसानों को भंडारित गेहूं का वाजिब दाम नहीं मिल सका है। अब जब नई फसल आने को तैयार है तो किसानों के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में चीनी आयात की सुगबुगाहट गन्ना किसानों की परेशानी का सबब बनी है। भारतीय किसान आंदोलन के नेता नरेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि कई वर्षों से सस्ते में गन्ना बेचने को मजबूर किसान इस सीजन में चीनी मूल्य बेहतर होने से संतुष्ट है। इसी कारण किसानों का भुगतान संकट गत वर्ष जैसा नहीं है। इसके बाद भी बकाया मूल्य करीब छह हजार करोड़ रुपये हो चुका है। चीनी आयात से दाम गिरेंगे तो किसानों का भुगतान संकट फिर से विकट हो जाएगा।

महाराष्ट्र शुगर लाबी का दबाव : भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि चीनी आयात के लिए महाराष्ट्र की शुगर लाबी दबाव बना रही है ताकि इस सीजन में चीनी उत्पादन में पिछड़े महाराष्ट्र की चीनी मिलें आयात का लाभ उठा सकें। टिकैत का कहना है कि विदेश से चीनी आयात का डट कर विरोध किया जाएगा। किसान संघ के श्यामवीर सिंह का कहना है कि प्रदेश की चीनी मिलों को बचाने की जरूरत है। इस बार उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन बढ़ा है और इसका लाभ किसानों को मिलने की आस जगी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में चीनी का आयात नहीं करने की मांग की है।

नई सरकार की बढ़ेगी मुसीबत : आयात होने से चीनी में मंदी आने का किसानों को भी खमियाजा भुगतना होगा। गन्ना मूल्य भुगतान बढ़ेगा तो आने वाले प्रदेश सरकार के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसा होगा। इस पेराई सत्र में उप्र की मिलों में करीब 85 लाख चीनी उत्पादन होने की उम्मीद बंधी है।